INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)
(Int Peer Reviewed Journal)
Vol. 05, Issue 01, January 2025, pp : 1134-1036
e-ISSN : 2583-1062
Impact Factor : 7.001
www.ijprems.com
editor@ijprems.com

भारत से कृषि वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य (पोस्ट वल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन) एक अध्ययन

सोनू कुमार सैनी

शोधार्थी, श्री कुशाल दास विश्विद्यालय हनुमानगढ़, राजस्थान

सारांश

कृषि पर मुख्य रूप से ध्यान देने वाले राष्ट्र के रूप में मौजूद होने के बावजूद, जहां खेती का क्षेत्र लगभग 60 प्रतिशत आबादी को आजीविका के अवसर प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण 25 प्रतिशत का योगदान देता है, भारत वैश्विक कृषि व्यापार क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटा स्थान बनाए हुए है। वर्तमान में, कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी भागीदारी मात्र 1 प्रतिशत से कम है। 2005–06 की अवधि को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि कॉफी, चाय और मत्स्य पालन जैसी कृषि वस्तुओं ने भारत से कुल निर्यात का 10.95 प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से हिस्सा लिया।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) दुनिया भर के विभिन्न देशों के बीच व्यापार नियमों के जटिल वेब की देखरेख और विनियमन करने का काम करने वाली अद्वितीय वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। 1994 में इसकी शुरुआत ने भारत की सीमाओं के भीतर कृषि व्यापार के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की, जिससे संभावनाओं और चुनौतियों के एक नए युग की शुरुआत हुई। कृषि प्रगति को बढ़ावा देने की अनिवार्यता भारत के व्यापक विकास एजेंडे में सर्वोपरि स्थान रखती है, जिसका लक्ष्य विश्वव्यापी व्यापार क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर वैश्विक मंच पर देश की बाजार उपस्थिति को मजबूत करना है। उदारीकरण के व्यापक सुधारों की विशेषता वाला युग अतीत की संरक्षणवादी विचारधाराओं से एक स्पष्ट और विशिष्ट विराम का प्रतीक है, जो एक अधिक खुली और परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का संकेत देता है। फिर भी, भारत खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाता है, जहां अपने विशाल कृषि क्षेत्र को विश्व बाजारों के जटिल ताने–बाने में समेकित रूप से एकीकृत करने का काम बहुत बड़ा है और इसके लिए टिकाऊ विकास और समृद्धि के लिए ठोस प्रयासों और रणनीतिक योजना की आवश्यकता है (प्रेमचंद्र, 2005)।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में, सीमाओं के पार कृषि और खाद्य वस्तुओं के प्रवाह में बाधा डालने वाली बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में कई तरह के उपाय शामिल हैं जैसे कि टैरिफ, मात्रात्मक प्रतिबंध, और व्यापार के लिए कई अन्य बाधाएं जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता के माध्यम से संबोधित किया गया है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, बाजार में प्रथागत और नवीन दोनों तरह के उत्पादों की विविध रेंज को पूरा करते हुए, निर्यात प्रभावकारिता में वृद्धि की संभावनाओं से भरा एक आशाजनक परिदृश्य उभरता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने जटिल और व्यापक प्रावधानों की एक श्रृंखला को सावधानीपूर्वक तैयार करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया है, जो विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की जटिल और बहुआयामी दुनिया से संबंधित हैं, जो वैश्विक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये प्रावधान राष्ट्रों के बीच होने वाली व्यापार बातचीत के जटिल जाल को सुविधाजनक बनाने और उसकी देखरेख करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करते हैं, जिसमें शामिल सभी पक्षों के लिए एक निष्पक्ष और संतुलित खेल मैदान स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के आगमन और कृषि के क्षेत्र में इसके सावधानीपूर्वक तैयार किए गए प्रावधानों के कार्यान्वयन ने एक नए युग की शुरुआत की है, जो सभी हितधारकों की भलाई के लिए जब्त किए जाने और उनका उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा में असीम अवसरों से भरा हुआ है। हालांकि, इन आशाजनक अवसरों के साथ–साथ, वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र के सतत विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कई विकट चुनौतियां भी हैं, जिनका सामना सावधानी और रणनीतिक योजना के साथ किया जाना चाहिए।

भारत, अपने समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति के साथ, अपने व्यापक कृषि क्षेत्र को वैश्विक बाजार में पूरी तरह से शामिल करने के मामले में एक महत्वपूर्ण यात्रा का सामना कर रहा है। इस एकीकरण का रोडमैप जटिल और बहुआयामी है, जिसके लिए परंपरा और आधुनिकता के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है। आगे का अध्याय एक दिलचस्प कहानी की तरह सामने आता है, जो पाठकों को अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार के जटिल जाल के भीतर भारत की अद्वितीय स्थिति के बारे में विस्तृत और व्यापक जानकारी प्रदान करता है। आगामी अनुभाग एक आधार के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत के ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। इसके बाद, बाद का हिस्सा पिछले एक दशक में राष्ट्र द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों के जटिल विवरणों पर प्रकाश डालता है, कार्यान्वयन चरण के दौरान आने वाली चुनौतियों और सुधार एजेंडा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है जो अभी तक अनसुलझे हैं।

तालिका 5.1

विश्व व्यापार संगठन से पहले, उसके दौरान और उसके बाद कृषि वाणिज्य की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने वाले संकेतक।

विशिष्ट	1992–93से 1994–95	1995–96 से 1997–98	1998–99 से 2000–01	2001–02 से 2003–04
कृषि आयात	1190	1996	3272	4087
कृषि आयात	3725	6530	6060	7141
शुद्ध व्यापार	2534	4534	2788	3055

विभिन्न कृषि उत्पादों में बाजार हिस्सेदारी में भारत की गिरावट, जहां पहले अथुकोरला 1998, भगवती 1993 और श्रीनिवासन 1998 जैसे स्रोतों के अनुसार तुलनात्मक लाभ था, एक महत्वपूर्ण झटका रहा है। कृषि व्यापक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कुल व्यापारिक निर्यात का 13.4 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र का निर्यात भारत के समग्र निर्यात परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए, विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा निर्धारित प्रावधानों का लाभ उठाने और अन्य विकासशील देशों के साथ मजबूत सहयोग को बढ़ावा देने की अत्यधिक आवश्यकता है जो भारत के हितों के लिए अधिक अनुकूल हैं।

वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को भुनाने के लिए एक प्रमुख डोमेन के रूप में कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें अपार संभावनाएं हैं।

देश की व्यापार रणनीति का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक व्यापार क्षेत्र में कम से कम 1प्रतिशत या उससे अधिक की बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। पिछले कुछ दशकों में, कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर देने के साथ, देश के भीतर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है, जो पारंपरिक उत्पादों जैसे तम्बाकू, चाय, कॉफी, काजू, मसाले, कच्चा कपास, प्रीमियम बासमती चावल, आदि के निर्यात का लाभ उठाकर विदेशी राजस्व उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। भारत में

www.ijprems.com
editor@ijprems.com
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)
(Int Peer Reviewed Journal)
Vol. 05, Issue 01, January 2025, pp : 1134-1036
e-ISSN : 2583-1062
Impact Factor : 7.001

कृषि परिदृश्य में उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा होती है, जो व्यापार गतिविधियों के माध्यम से विकास और समृद्धि की संभावनाओं को रेखांकित करती है, जो निर्यात के अवसरों के विशाल भंडार को खोल सकती है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे निर्यात के अवसरों के विशाल भंडार को खोल सकती है, जैसा कि गुलाटी और उनके सहयोगियों द्वारा 1994 में किए गए मौलिक कार्य में उजागर किया गया था। आंकड़ों के विश्लेषण से कृषि निर्यात और आयात के कुल मूल्य के बीच एक बड़ा अंतर पता चलता है, जो देश के व्यापार संबंधों की जटिल गतिशीलता और इसके आर्थिक एजेंडे को चलाने वाली रणनीतिक अनिवार्यताओं पर प्रकाश डालता है।

2001-02	297.3	162.6
2002-03	346.5	176.1
2003-04	372.7	219.7
2004-05	416	128.1
2005-06	492.2	215
2006-07	624.1	296.4
2007-08	777.7	297.8

चित्र 5.1

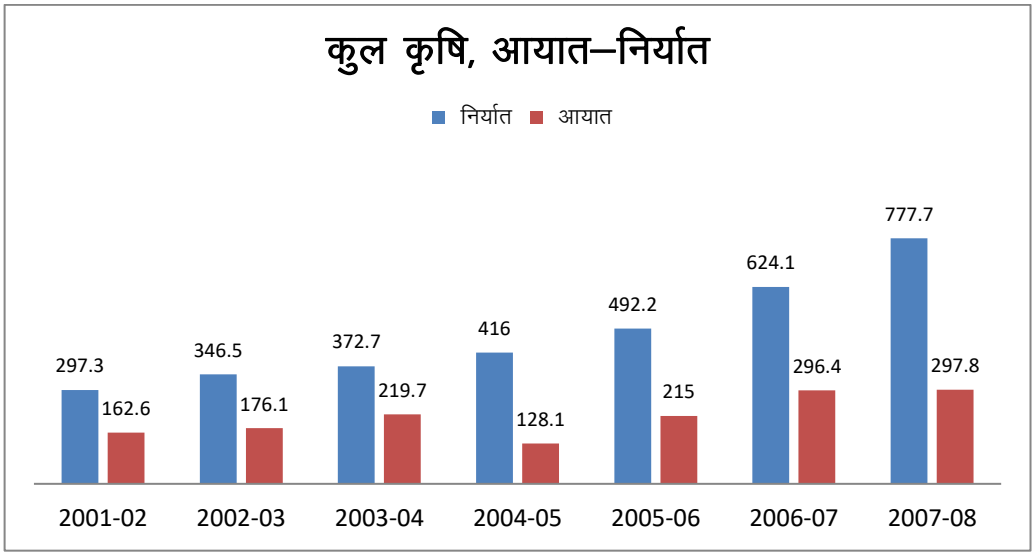

स्रोत : एग्लेन्स 2008 में कृषि सांख्यिकी

5.3 विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के भीतर कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं और चुनौतियां –

हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, जो वैश्विक बाजार में इसके महत्व को प्रदर्शित करती है। निर्यात किए जा रहे कृषि उत्पादों की विविधता काफी विविध है, जिनमें चाय, तिलहन, फल, सब्जियां, मसाले, तम्बाकू, जानवरों के बाल और वनस्पति तेल शामिल हैं। इस निर्यात उद्योग में विकास की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि यह दुनिया भर के विभिन्न देशों तक अपनी पहुंच बढ़ाता है। विशेष रूप से, वर्तमान फोकस में चीन जैसे देशों को चावल और गेहूं का निर्यात करना शामिल है, जो व्यापार क्षितिज के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अनाज निर्यात करने के अवसर व्यापक हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जैसे–जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ता है और घरेलू बाजार तेजी से उदारीकरण के दौर से गुजर रहा है, भारत वैश्विक व्यापार क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित करने के लिए तैयार है। इन प्रगति के बावजूद, कृषि क्षेत्र में सुधारों की गति अपेक्षाकृत सुस्त रही है, खासकर आर्थिक परिवर्तनों के शुरुआती चरणों में। सरकार का दृष्टिकोण सतर्क रहा है, जो खाद्य सुरक्षा, छोटे पैमाने के किसानों की आजीविका, पर्यावरणीय स्थिरता और अन्य संबंधित कारकों जैसे पहलुओं पर व्यापार सुधारों के संभावित प्रभावों पर चिंताओं को दर्शाता है।

देश के संपूर्ण निर्यात राजस्व का लगभग सातवां हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, जो अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। इस तथ्य के बावजूद कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में कृषि उद्योग का विस्तार सराहनीय रहा है, यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश किसानों के पास भूमि जोत का आकार 2–हेक्टेयर से कम है। इसके अलावा, समग्र फसल क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, जो कृषि पद्धतियों में विविधीकरण और नवाचार की आवश्यकता को उजागर करता है। मौजूदा सिंचाई अवसंरचना को कृषि क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त माना जाता है, जो टिकाऊ विकास के लिए एक चुनौती है। इसके अतिरिक्त, किसानों के एक बड़े हिस्से ने अभी तक वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से मिलने वाले लाभों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया है, जो इस क्षेत्र में अप्रयुक्त संभावनाओं को दर्शाता है। इसलिए, कृषि उत्पादन की निरंतर प्रगति को सुनिश्चित करना खुद को एक विकट उपक्रम के रूप में प्रस्तुत करता है जिसके लिए व्यापक रणनीतियों और ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है।

वैश्विक कृषि कमोडिटी बाजार में निर्यातक के रूप में भारत की उपस्थिति मुख्य रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चावल, मसाले, सोया भोजन, काजू, चाय और कॉफी जैसी कुछ ही वस्तुएं सबसे अलग हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार घाटे का लगातार विस्तार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के रूप में समग्र कृषि निर्यात को बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता को रेखांकित करता है। नतीजतन, भारत के लिए आगामी वर्षों में रणनीतिक रूप से अपने कृषि क्षेत्र को फिर से संगठित करना अनिवार्य हो जाता है, न केवल बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, बल्कि

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)
(Int Peer Reviewed Journal)
www.ijprems.com
editor@ijprems.com
Vol. 05, Issue 01, January 2025, pp : 1134-1036
e-ISSN : 2583-1062
Impact Factor : 7.001

व्यापक आर्थिक परिदृश्य के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसा कि 2001 में NAAS की रिपोर्ट में बताया गया है।

भारत के कृषि निर्यात को तीन विस्तृत समूहों में वर्गीकृत किए जाने की संभावना है।

1. कच्चे उत्पादों का निर्यात
2. आंशिक रूप से संसाधित माल भेजना
3. संसाधित और खाने के लिए तैयार उत्पादों का निर्यात।

चाय, कॉफी, मसाले और तम्बाकू जैसी पारंपरिक निर्यात वस्तुओं से निर्यात आय मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज गिरावट के परिणामस्वरूप काफी प्रभावित हुई। इस गिरावट का इन वस्तुओं से उत्पन्न राजस्व पर बड़ा प्रभाव देखा गया, यह देखते हुए कि ज्यादातर मामलों में, निर्यात की मात्रा में कोई समान कमी नहीं आई। विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना के बाद कृषि के वैश्विक उदारीकरण की घटना को व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात के स्तर को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में माना गया। उदारीकरण में वृद्धि के संभावित लाभों पर इस परिप्रेक्ष्य को राजीव आर ठाकुर ने 2005 के एक प्रकाशन में व्यक्त किया था।

संदर्भ –

1. अथुकोरला, प्रेमा–चंद्र। (1998)। एशियाई विकास में व्यापार नीति के मुद्दे। लंदन : रूटलेज.
2. अप्टन, एम. (2000)। लघु धारक कृषि के लिए पशुधन क्रांति के निहितार्थ : केन्या में दूध और पोल्ट्री का एक केस स्टडी। एजीएल सेवा के लिए रिपोर्ट। रोम : एफएओ
3. कालीरजन, कलियप्पा और कन्हैया सिंह (2006)। भारत और कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता (ए–ओ–ए)। में : इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स कॉन्फ्रेंस, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया, 12–18 अगस्त, 2006
4. कौर, कुलजीत और अरनीत कौर। (2009)। डब्ल्यूटीओ व्यापार व्यवस्था और भारतीय कृषिरू : चुनौतियाँ, निहितार्थ और सिफारिशें। अहमद, रईस (सं.) में। डब्ल्यूटीओ और भारतीय कृषि : अवसर, समस्याएँ और चुनौतियाँ, नई दिल्ली : मित्तल प्रकाशन।
5. गुलाटी और शर्मा, (1994), एग्रीकल्चर अंडर गैटः व्हाट इट होल्ड्स फॉर इंडिया। इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम। 29, पृ. 1857–1863, पृ. 1861.
6. गुलाटी, ए. और टी. केली (1999): व्यापार उदारीकर.ा और भारतीय कृषि। नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. चंद, रमेश (2005). डब्ल्यूटीओ के बाद के दशक के दौरान भारत का कृषि व्यापार : बातचीत के लिए सबक। में : सेमिनार 'ऑफ द ब्लॉक्स टू हांगकांग : कंसर्न्स एंड नेगोशिएटिंग ऑप्शन्स ऑन एग्रीकल्चर एंड एनएएमए' सेंटैड, 22 जुलाई, 2005, नई दिल्ली।
8- चन्द्रशेखर, सी.पी., जयति घोष और पार्थप्रतिम पाल (2003)। मुक्त व्यापार में हरित बाधा। दिनांक 12 मार्च 2010 को पुनः प्राप्त किया गया। यहां उपलब्ध है : http://www-networkideas-org/focus/feb2003/fo03_Free_Trade-htm
9. प्रेमा–चंद्र अथुकोरला। (2005)। भारत में कृषि व्यापार नीति सुधार। दक्षिण एशिया आर्थिक जर्नल, 6य 23.
10. भगवती, जगदीश। (1993)। संक्रमण में भारतः अर्थव्यवस्था को मुक्त करना। ऑक्सफोर्ड : क्लेरेंडन प्रेस.